

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 14 नवम्बर, 2011

विषय:— लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को जिनकी दुकानों से सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या 50 से लेकर 300 राशन कार्ड तक है को प्रतिमाह प्राप्त हो रहे लाभांश को सम्मिलित करते हुए ₹ 3,000/- प्रतिमाह मानदेय दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्यायुक्त के पत्र सं० 339/आ०खा०पूर्ति/56/2011 दिनांक 05 जुलाई, 2011 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर शासन द्वारा किये गये सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को वर्तमान में शासनादेश सं० 195/11-XIX-2/89 खाद्य/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 से दिये जा रहे लाभांश को सम्मिलित करते हुये अधिकतम ₹ 3,000/- (रु० तीन हजार) प्रतिमाह मानदेय निम्न तालिका के अनुसार दिये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा, प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या	दुकानों की संख्या	कुल लाभांश प्रति विक्रेता	प्रति विक्रेता प्रस्तावित न्यूनतम लाभांश (3000- कालम 4)
1	2	3	4	5
1	50	333	552.46	2447.55
2	100	1676	963.79	2036.21
3	150	1423	1445.69	1554.32
4	200	1134	1927.58	1072.42
5	250	705	2409.48	590.53
6	300	669	2891.37	108.63

क्रमशः 2

अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाभांश को कम करते हुये मानदेय की शेष धनराशि का भुगतान कॉलम नं० 05 में अंकित धनराशि के अनुरूप 300 एवं इससे कम कार्ड वाले सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त व्यवस्था भारत सरकार में विचाराधीन "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के लागू होने तक ही प्रभावी रहेगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के पश्चात उक्त जारी आदेश तत्समय प्रभावी "खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के प्राविधानों के अधीन रहेगा।

भुवदीय,

(सुबर्द्धन) 14/11/11

अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)

संख्या 620/11-XIX-2/89 खाद्य/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री को संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
8. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समन्वयक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन) 14/11/11

अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)